THE MINISTER OF INFORMATION AND EROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) The number of TV licences in force as on 31-12-1972 was 6,76,615.

- (b) and (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha.
- (d) and (e). The Wireless Licence Inspector first issues a notice to the defaulters pointing out the legal consequences and requesting them to get their licences renewed within 15 days of the receipt of the notice. Where there is no response, the Inspector pays a personal visit and explains the provision of the Law to the holder of the TV set, Licences who fail to get their licences renewed, in spite of these efforts, are presecuted. Anti-evasion drives are also organised to detect sets without licences.

Command with the Forg Accompace and Communication Corporation for Supply of Satellites and Allied Enquipment

4944. SHRI SARAT KAR:

SHRI AHMED M. PATEL:

Will the Minister of SPACE be pleased to state:

- (a) whether the Union Government have entered into a contract with the Ford Aerospace and Communication Corporation of the United States for the supply of satellites and allied equipment for the Indian National Satellite system; and
 - (b) if so, the details thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir.

(b) On July 21, 1978, the Department of Space has awarded a firm fixed price contract for the two TNSAT-I flight spacecraft and allied equipment and services to the Ford Aero-

space and Communications Corporation of the U.S.A. The INSAT-I spacecraft, first of which is to be supplied 28 months from July 21, 1978, and the second 31 months from that date are multi-purpose geo-stationary spacecraft for providing operational telecommunications, mateorology and television services in the country. The contract also covers supply of satellite control equipment for the Master Control Facility being established in India, certain launch support services such as orbit raising and deployment of the spacecraft in final orbit and initial manning of the Master Control Facility for 180 days following the launch of the first spacecraft during which the Master Control Facility operation is to be gradually passed on to the Department of Space personnel. The fixed firm delivery price of the Contract is US \$ 60.496 raillion, i.e., about Rs. 50.44 crores in terms of the prevailing rate of exchange. In addition, under the Contract, the Contractor may become entitled to earn additional amounts upto US \$ 8.5 million, i.e., about Rs. 7.9 esores, depending on the actual postormance of the two spacecraft in geo-stationary orbit during their respective 7 year design lives.

Electrification of Villages in Meghalasa

4945. SHRI P. A. SANGMA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

- (a) total number of villages electrified in Meghalaya (district-wise) so far; and
- (b) total amount sanctioned for rural electrification during this financial year?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a). Out of a total of 4,583 villages in Meghalaya 425 were electrified as on 21st July 1978. District-wise details are as follows

•		176
	•	50
		40
	٠	43
		116
		445
	•	

(b). The Annual Plan for 1978-79 provides for an allocation of Rs. 3.06 crores for rural electrication in Meghalaya. Details are as follows:---

		Rs.	crores
REC No	rmal Programm	e .	1 · 22
EHT Tra	ansmission Lines		o· 75
MNP		•	1.09
	Total .	• _	3.06

बाबीज उद्योगों की स्थापना करने वाले ब्रीब्रोनिक गृहों के नाम

4946. भी सुरेना शासमाः क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कुश करेंगे कि:

- (क) बीखोगिक गृहों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के प्रस्ताम को किला सीमा तक कियान्वित किया गया है ग्रयका कियान्वित किया जायेगा जैसे कि भारत सरकार द्वारा घोषित श्रीयोगिक नीति में परिकल्पना की गई है :
- (ख) कौन-कौन से भौद्योगिक गृह प्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिये भव तक धारों भागे हैं भीर उन्होंने इस प्रयोजन के लिये किन-किन स्थानों का चयन किया है: धौर
- (म) क्या बिहार के प्रामीण क्षेत्रों में भी भी क्षेत्रिक प्रसार का ऐसा कोई कार्यक्रम

भिषानियत किया जायेगा सीर वदि हो, ो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? .

उद्योग मंत्रालय में शक्य मंत्री (श्रीमती धाना नाहति) (क) से (ग): भीशोगक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए ग्रीशोगिक चरानों से प्राप्त प्रस्ताबों पर जिनकें सामीक क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले उद्योग भी शामिल हैं. 23 दिसम्बर, 1977 को संसद के सामने प्रस्तत किये गए भौद्योगिक नीति सम्बन्धी विवरण के धनुसार विचार किया जाता है। भौद्योगिक नीति सम्बन्धी विवरण में यह स्पष्ट किया गया है कि 1971 की जनगणना के प्रनुसार 5 लाख से प्रधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों तथा दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले विभिन्न महा-नगरों की सीमा में नये भौद्योगिक एककों को भीर ध्रधिक लाइसेंस जारी नहीं किये आर्थेंचे। इस निर्णय को प्रभाव में लाने के लिए दिनांक 26 धप्रैल, 1977 को एक म्रपेक्षित मधिसूचना भी जारी कर दी गई है। फरवरी, 1973 के नीति सम्बन्धी विवरण में उल्लिखित एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार के अन्तर्गत ग्राने वाले उप-कमों पर लगाए गए, प्रतिबन्ध लाग् रहेंगे तचा उन्हें उद्योग (विकास तथा विनियमन) श्रधिनियम के लाइसेंसीकरण उपबन्धों से कोई छट नहीं दी जाएगी।

सभी भौद्योगिक लाइसेंसों संबंधी भ्यौरे जिनमें उपक्रमों का नाम, उत्पादन की वस्त, क्षमता. स्थापना-स्थल बादि होते हैं, "बीकली-बलेटिन ग्राफ इण्डस्टियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट" "इण्डियन ट्रेड जनरत्स" तथा मन्यली लिस्ट ग्राफ "लैंटर्स ग्राफ इन्टैट एण्ड इण्डस्ट्यिल लाइसेंसेंज" में प्रकाशित किए जाते हैं । इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

बिहार राज्य के उपक्रमों को 1977 तका 1978 (जनवरी-जून) में विये नये